



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]
No. 38]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 1992/माघ 2, 1913
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 1992/MAGHA 2, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

विदेशी कर प्रभाग

अधिमूर्चना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1992

आयकर

सा.का.नि. 60(अ).--दोहरे कराधान का अपवर्जन करने के लिए और आय पर करों को बाबत राजवित्तीय अपवर्जन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और आस्ट्रेलिया की सरकार के बीच हमारे उपावह करार, उक्त करार के अनुच्छेद 28 के पैरा (1) के अनुसार एक दूसरे को यह अधिपूर्वित करते हुए कि ऐसी बातों में से अंतिम कर दी गई है जो उक्त करार के भारत में और आस्ट्रेलिया में विधि का बल देने के लिए आवश्यक है, टिप्पणी के आदान-प्रदान पर 30 दिसंबर, 1991 को प्रवृत्त किया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अधिकार अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

उपावह

भारत गणराज्य की सरकार

और

आस्ट्रेलिया सरकार

के बीच

आय पर करों के सम्बन्ध में

दोहरे कराधान के परिहार

और

राजस्व अपवर्जन को रोकने के

लिए करार

भारत गणराज्य की सरकार और आस्ट्रेलिया सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान तथा राजस्व अपवर्जन को रोकने के लिए एक करार निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार सहमत हैं :

अनुच्छेद-1

वैयक्तिक विषय-क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संबंधित राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. विद्यमान कर जिन पर यह करार लागू होगा, इस प्रकार हैं:

(क) आस्ट्रेलिया में:

आस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के संघीय कानून के अंतर्गत लगाया गया आयकर और पेट्रोलियम संसाधनों के अन्वेषण और उनके उपयोग से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के संबंध में संसाधन किया गया कर;

(ख) भारत में:

(i) आयकर जिसमें उस पर लगाया गया कोई अधिभार; और

(ii) कंपनियों के प्रभार्य लाभों पर लगाया गया अतिरिक्त।

2. यह करार, किन्हीं भी समरूप अथवा सारन: जैसे ही करें पर लागू होगा जो आस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के संघीय कानून अथवा भारत के गणराज्य के कानून के अंतर्गत इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद वर्तमान करें के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने राज्यों के कानूनों में उन करें के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना एक दूसरे को देने जिनके संबंध में यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के उद्देश्यों के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अर्थ-हित न हो;

(क) "आस्ट्रेलिया" शब्द में, अब उसे भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त किया जाए निम्नलिखित से मिल सही बाह्य राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं:

(i) नोर्थकोक द्वीप राज्यक्षेत्र;

(ii) क्रिसमस द्वीप राज्यक्षेत्र;

(iii) कोकास (कीलिंग) द्वीप राज्यक्षेत्र;

(iv) ग्रासमोर तथा कार्टियर द्वीप राज्यक्षेत्र;

(v) हार्ड द्वीप और मैक डोनाल्ड द्वीप राज्यक्षेत्र; तथा

(vi) कोरल समुद्र द्वीप राज्यक्षेत्र;

और इसमें आस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय सीमाओं से लगा कोई ऐसा क्षेत्र शामिल है (उसमें उप-पैरा-ग्राफ (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र भी शामिल हैं) जिनके संबंध में आस्ट्रेलिया का कोई कानून जो फिलहाल प्रवृत्त हो और जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के समरूप हो और जो महाद्वीपीय शैल के समुद्रतल और भवम्बा के प्राकृतिक संसाधनों के किसी उपयोग से संबंधित हो;

(ख) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है भारत का राज्यक्षेत्र और उसमें क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का आकाश क्षेत्र और साथ ही अन्य कोई समुद्री क्षेत्र शामिल है जिन पर भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुता संपन्न अधिकार, अन्य अधिकार और अंतर्गत अधिकार हैं;

(ग) "संविदाकारी राज्य", "संविदाकारी राज्यों में से कोई एक राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" शब्दों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार आस्ट्रेलिया सरकार अथवा भारत सरकार अभिप्रेत हैं जिन्होंने इस करार को निष्पन्न किया है;

(घ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय तथा कोई अन्य ऐसी सत्ता शामिल है जिसे

कर प्रयोजनों के लिए कर योग्य यूनिट के रूप में माना जाता है;

(ङ) "कंपनी" शब्द से ऐसा कोई भी निगमित निकाय अथवा ऐसी कोई सत्ता अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है;

(च) "संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से अभिप्रेत है संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार आस्ट्रेलिया के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अथवा भारत के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम;

(छ) "कर" शब्द से संदर्भ की अपेक्षानुसार आस्ट्रेलियाई कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है;

(ज) (i) "आस्ट्रेलिया कर" पद से अभिप्रेत है आस्ट्रेलिया द्वारा लगाया गया कर; और

(ii) "भारतीय कर" पद से अभिप्रेत है भारत द्वारा लगाया गया कर;

जो ऐसा कर है जिस पर अनुच्छेद 2 के कारण यह करार लागू होता है लेकिन इस पद में कोई बंड अथवा कोई जमाता अथवा कोई व्याज शामिल नहीं है जो कर से संबंधित दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत लगाया गया हो;

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है, आस्ट्रेलिया के मामले में कराधान आयुक्त अथवा आयुक्त का कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि और भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त संचालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि; और

(ञ) भारतीय कर से संबंधित "आय का वर्ष" पद का अभिप्राय है "पूर्ववर्ती वर्ष", जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित किया गया है।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू करने के संबंध में, किसी भी शब्द का, जो इस करार में परिभाषित नहीं है, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न की गई हो, वही अर्थ होगा जो उस करों के संबंध में समय-समय पर प्रवृत्त उस राज्य के कानूनों के अधीन होता है जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद-4

निवास-स्थान

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, यदि कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है तो वह व्यक्ति उसके कर प्रयोजनों के लिए उस संविदाकारी राज्य का निवासी होगा, लेकिन, यदि कोई व्यक्ति इस करार के प्रयोजनों के लिए किसी संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है तो उस व्यक्ति पर केवल उस राज्य के कानूनों से प्राप्त आय के संबंध में ही उस राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. जहां, पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उस व्यक्ति की हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निर्णित की जाएगी:

(क) वह व्यक्ति केवल उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उस व्यक्ति को कोई स्थायी निवास उपलब्ध हो;

(ख) यदि उस व्यक्ति को दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध है अथवा उन दोनों में से किसी में भी उपलब्ध नहीं है तो वह व्यक्ति केवल उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उस व्यक्ति के व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर है (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र)

इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी व्यक्ति की नागरिकता के साथ ही साथ उस व्यक्ति का स्थायी निवास उस संविदाकारी राज्य के साथ उस व्यक्ति के व्यक्तिगत तथा आर्थिक संबंधों की गहराई (डिग्री) का निर्धारण करने के कारक होंगे।

3. जहाँ पैरा (1) के उपबंधों के कारण, किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसे केवल उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित हो।

अनुच्छेद-5

स्थायी संस्थापन

1. इस क़रार के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी संस्थापन" शब्दों से कारख़ार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से उद्यम का कारख़ार संपूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" शब्दों के अर्थ-विस्तार के अंतर्गत विशेषतः निम्न-लिखित आते हैं :—

- (क) प्रबंध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारख़ाना;
- (ङ) कोई कर्मशाला;
- (च) खान, तेल अथवा गैस कूप, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई स्थान;
- (छ) दूसरों के लिए संश्लेषण सुविधाएं प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति का कोई मालमोदम;
- (ज) कोई फ़ार्म, बाग़ान अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि, चारागाही, वनविद्या अथवा बाग़ान से संबंधित कार्यकलाप किए जाते हैं;
- (झ) बिक्री स्थान के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले अथवा आदेश प्राप्त करने अथवा मांगे जाने के लिए परिसर;
- (ञ) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना अथवा संयंत्र अथवा उपस्कर जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा निष्कर्षण के लिए किया जाता है;
- (ट) कोई सत्रन स्थल अथवा निर्माण, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा किसी ऐसे स्थल अथवा परियोजना के संबंध में पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जहाँ वह स्थल अथवा परियोजना चल रही है अथवा वे कार्यकलाप (पूयक रूप से अथवा अन्य स्थलों, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के साथ) छः महीने से अधिक अवधि के लिए जारी रहते हों।

3. किसी उद्यम का दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन होता और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारख़ार चलाया जाना माना जाएगा यदि :

- (क) उद्यम द्वारा, उसके लिए अथवा उसकी संविदा के अंतर्गत उस राज्य में महत्वपूर्ण उपस्कर प्रयोग किए जा रहे हों;
- (ख) वह उस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा निष्कर्षण के संबंध में उस राज्य में कार्यकलाप चलाता हो; अथवा
- (ग) वह दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के बीच कर्मचारियों अथवा अन्य कर्मिकों के माध्यम से सेवाएं, जिनमें प्रबंधकीय सेवाएं और अनुच्छेद 12 के उप-

पैराग्राफ (3) (ज) से (ट) तक में उल्लिखित सेवाएं भी शामिल हैं लेकिन अदायगी अथवा श्रुतियों के संबंध में वे सेवाएं शामिल नहीं हैं जो अनुच्छेद 12 में यथा-परिभाषित रायल्टियां हैं, प्रदान करता हो, लेकिन यदि वे सेवाएं उस राज्य के ही भीतर निम्नानुसार प्रदान की जाती हैं :

- (i) किसी 12 माह की अवधि के भीतर कुल 90 दिनों से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए ; अथवा
- (ii) दूसरे उद्यम के लिए यदि दोनों उद्यमों के बीच प्राप्त में अनुच्छेद 9 के उप पैराग्राफ (1) (क) और (ख) में वर्णित संबंध है।

4. कोई उद्यम केवल निम्नलिखित कारण से कोई स्थायी संस्थापन होता नहीं माना जाएगा :

- (क) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के पूर्णतः भण्डारण अथवा उसके प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- (ख) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखना ;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजन के लिए ही उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखना ;
- (घ) उद्यम के लिए केवल माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदने अथवा भुजना एकत्र करने के प्रयोजन के लिए कारख़ार का निश्चित स्थान रखना ; अथवा
- (ङ) उद्यम के लिए केवल विज्ञापन के प्रयोजनार्थ सूचना देने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अथवा इसी प्रकार के कार्य-कलापों के लिए जो प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के हों, कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना।

तथापि, इस पैराग्राफ के पूर्ववर्ती उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जहाँ संविदाकारी राज्यों में से किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखता हो।

5. कोई व्यक्ति, जो स्वतंत्र हैसियत के उस एजेंट से भिन्न हो जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से किसी एक संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा हो, तो उसे प्रथमोक्तिस्थित राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन होता माना जाएगा, यदि :

- (क) उस व्यक्ति को उस राज्य में उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार है और वह अभ्यासतः इसका प्रयोग करता है, जब तक कि उस व्यक्ति के कार्यकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं की खरीद तक सीमित नहीं हों ;
- (ख) उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, परन्तु वह उस राज्य में अभ्यासतः उस उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का भण्डार रखता हो जिसमें से वह व्यक्ति उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल अथवा पण्य वस्तुओं का परिवान करता करता है ;
- (ग) वह व्यक्ति उस राज्य के स्वतः उद्यम के लिए अथवा उद्यम के लिए और नियंत्रण करने वाले अन्य उद्यमों अथवा नियंत्रित किए गए अन्य उद्यमों अथवा इसी प्रकार के सामान्य नियंत्रण के अधधीन उस उद्यम के लिए पूर्णतः अथवा मुख्यतः आर्बैर प्राप्त करता है; अथवा

(ग) इस प्रकार के कार्य करने में, वह व्यक्ति उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं का उद्यम के लिए उस राज्य में विनिर्माण करता हो अथवा उनको संसाधित करता हो।

6. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है चाहे वह व्यक्ति किसी दलाल अथवा किसी एजेंट के रूप में कारोबार को सामान्य रूप से कर रहा हो। तथापि, जब ऐसे किसी दलाल अथवा एजेंट के कार्यकलाप स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उद्यम की ओर से और नियंत्रण करने वाले और नियंत्रित किए गए उद्यम की ओर से अथवा इसी प्रकार के सामान्य नियंत्रण के माध्यम से उस उद्यम की ओर से पूर्णतः अथवा मुख्यतः किए जाते हैं, इस पैराग्राफ के अर्थों में उस व्यक्ति को कोई दलाल अथवा एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाला व्यक्ति नहीं समझा जाएगा।

7. इस तथ्य से कि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो दूसरे राज्य में (चाहे स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार चलाती है, उन दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी स्वतः दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

8. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में बताए गए सिद्धांत इस प्रकार के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ (5) और अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ (5) के प्रयोजनों के लिए यह निर्धारण करने के लिए लागू होंगे कि क्या दोनों संविदाकारी राज्यों के बाहर कोई स्थायी संस्थापन है और क्या एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के न होने पर कोई उद्यम किसी एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन रखता है।

अनुच्छेद-6

वास्तविक सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) से आय

1. वास्तविक सम्पत्ति से आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें वह सम्पत्ति स्थित है।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "वास्तविक सम्पत्ति" - पद का अर्थ है :

(क) आस्ट्रेलिया के मामले में, इसका अर्थ यह होगा जो आस्ट्रेलियाई कानूनों के अन्तर्गत लगाया जाता हो और जिसमें वे शामिल होंगे :

(i) भूमि का कोई पट्टा और भूमि में अथवा उस पर कोई अन्य हित, चाहे वह विकसित हो अथवा नहीं हों; और

(ii) संचालन के लिए प्रतिकूल के रूप में परिवर्तनीय अथवा स्थित भुगतान प्राप्त करने का अधिकार या खनिज अथवा अन्य भण्डारों, तेल अथवा गैस कूपों, खदानों अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण अथवा उपयोग के अन्य स्थानों के संबंध में कार्य करने अथवा खोज करने का अधिकार।

(ख) भारत के मामले में, इसका अर्थ ऐसी सम्पत्ति से है जो भारत के कानूनों के अनुसार अचल सम्पत्ति है और उसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) अचल सम्पत्ति के उप-साधन के रूप में सम्पत्ति ;

(ii) ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति के संबंध में सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हैं ;

(iii) अचल सम्पत्ति को भांगने और संचालन के लिए प्रतिकूल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत भुगतान प्राप्त करने के अधिकार

या खनिज अथवा अन्य भण्डारों, तेल अथवा गैस कूपों, खदानों अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण अथवा उपयोग के अन्य स्थानों के लिए काम करने अथवा उनके संबंध में खोज करने का अधिकार।

3. पैराग्राफ (2) के किसी भी पैराग्राफ में उल्लिखित भूमि का कोई पट्टा, भूमि में अथवा उसके ऊपर कोई अन्य हित और कोई अधिकार अथवा सम्पत्ति को ऐसे स्थान पर स्थित माना जाएगा जहाँ भूमि, खनिज अथवा अन्य भण्डार, तेल अथवा गैस कूप, खदानें प्राकृतिक संसाधन अथवा सम्पत्ति, जैसा भी मामला हो, स्थित हो अथवा जहाँ अन्वेषण कार्य किया जाता हो।

4. पैराग्राफ (1) के उपबंध वास्तविक सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से प्राप्त होने वाली आय पर लागू होंगे।

5. पैराग्राफ (1), (3) और (4) के उपबंध, किसी उद्यम की वास्तविक सम्पत्ति से अर्जित आय पर और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त वास्तविक सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

कारोबार से लाभ

1. किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, किन्तु केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो :

(क) उस स्थायी संस्थापन; अथवा

(ख) उन दूसरे राज्य में उसी भांति के अथवा उसी प्रकार के माल अथवा पण्य वस्तुओं का बिक्री करता हो अथवा उसी भांति अथवा उसी प्रकार के अन्य व्यावसायिक कार्यकलाप करता हो जैसे कि उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से चलाए जाते हों।

2. पैराग्राफ (3) के उपबंधों के अर्थों में रहते हुए, जो एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार करता हो, उस स्थायी संस्थापन को वह लाभ प्राप्त हुआ समझा जायेगा जिसके प्राप्त होने की उस स्थिति में अपेक्षा रहती जब वह उन्हीं अथवा वैसी ही परिस्थितियों में उन्हीं या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निधिवन और अपना उद्यम होता और उस उद्यम के साथ जिसका यह स्थायी संस्थापन है अथवा दूसरे लक्ष्यों के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता अथवा साथ यह कारोबार करता है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में, उस संविदाकारी राज्य में जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है कर से संबंधित कानून की परि-सीमाओं के अनुसार उद्यम के उन खर्चों की कटौतियों की स्वीकृति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए खर्च किए गए अथवा हैं (इनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं) चाहे इन्हें उस संविदाकारी राज्य में खर्च किया गया हो जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों।

4. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या पण्य वस्तुएं खरीदी गयी हैं।

5. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कराधान प्राधिकारी किसी स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों की सही रकम का निर्धारण करने में असमर्थ

है अथवा उस प्राधिकारी द्वारा उसका पता लगाने में प्रस्तावार्थ कठिनाइयाँ पेश आती हैं, तो वहाँ इस अनुच्छेद में वर्णित किसी भी बात का किसी व्यक्ति की कर की देनदारी का निर्धारण करने के संबंध में उस राज्य के किसी कानून को लागू करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद के सिद्धांतों के अनुसार उस सीमा तक कानून को लागू किया जाएगा जहाँ तक उस प्राधिकारी को उपलब्ध सूचना अनुमति प्रदान करती हो।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत कोई उचित अथवा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहाँ लाभों में आय की वे मदें शामिल हों, जिनका हम करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया हो, तो वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंधों पर इस अनुच्छेद के उपबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. इस अनुच्छेद में वर्णित किसी भी बात का अतिवासियों द्वारा बीमे से प्राप्त किए गए लाभों पर लगाए गए कर के संबंध में किसी संविदाकारी राज्य के किसी कानून के लागू होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बशर्ते कि यदि इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को दोनों संविदाकारी राज्यों में लागू संगत कानून भिन्न हो गया हो (अन्यथा गोन विषय में जिससे कि हमके सामान्य गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े), तो संविदाकारी राज्य इस पैराग्राफ के किसी संशोधन के लिए, जो भी उचित हो, सहमत होने की दृष्टि से एक दूसरे से परामर्श करेंगे।

9. जहाँ:

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी प्रत्यक्षतः अथवा अधिक मध्यस्थ न्यास सम्पदाओं के माध्यम से किसी ऐसे न्यास सम्पदा से मिला, जो उस दूसरे राज्य में किसी कंपनी के रूप में कर प्रयोजनों के लिए मानी जाती है, किसी न्यास संपदा के मालिक द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में चलाए गए किसी उद्यम के व्यापारिक लाभों के किसी हिस्से के लिए लाभ का हकदार है; और

(ख) उस उद्यम के संबंध में, उस न्यासी का, अनुच्छेद 5 के सिद्धांतों के अनुसार, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन हो;

तो मालिक द्वारा चलाए गए उद्यम को उस निवासी द्वारा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से चलाया गया एक व्यवसाय माना जाएगा और व्यावसायिक लाभों के उस हिस्से को उस स्थायी संस्थापन के कारण हुआ माना जाएगा।

अनुच्छेद--8

जलयान तथा वायुयान

(1) किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालन में संबंधित निधियों पर प्राप्त ब्याज सहित, जलयान अथवा वायुयान के संचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उसी राज्य में लगेगा।

(2) पैराग्राफ (1) के उपबंधों के होने हुए भी, ऐसे लाभों पर कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में लगेगा, जहाँ ऐसे लाभ केवल उस दूसरे राज्य में स्थित स्थानों तक सीमित जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त होते हैं।

(3) पैराग्राफ (1) और (2) के उपबंध किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी पूल सेवा, किसी संयुक्त परिवहन संचालन संगठन अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भागीदारी के माध्यम से जलयान अथवा वायुयान के संचालन से प्राप्त किए गए लाभों के हिस्से के संबंध में लागू होंगे।

(4) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी एक संविदाकारी राज्य में एक स्थान से उसी राज्य के किसी अन्य स्थान पर जलयान अथवा वायुयान द्वारा यात्रियों, पशुधन, डाक, माल अथवा अन्य वस्तुओं को भुलाई से प्राप्त होने वाले लाभों को केवल उस राज्य में स्थित स्थानों तक सीमित जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त लाभों के रूप में समझा जाएगा।

अनुच्छेद--9

सम्बद्ध उद्यम

(1) जहाँ:

(क) किसी एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, निबंधन अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सहभागी होता है; अथवा

(ख) वही व्यक्ति किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, निबंधन अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सहभागी होते हैं,

और दोनों ही मामलों में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें लागू होती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हों जो कि एक दूसरे के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से संबंध रखने वाले स्वतंत्र उद्यमों के बीच में लागू हो सकती हैं, तो ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की वशा से, उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु जो उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और उस पर तबनुसार कर लगाया जा सकेगा।

(2) इस अनुच्छेद का कोई भी भाग, किसी व्यक्ति की कर देयता को निर्धारित करने से संबंधित किसी संविदाकारी राज्य के किसी कानून को लागू करने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इसमें उन मामलों का निर्धारण भी शामिल है जहाँ पर किसी उद्यम के कारण होने वाले आय का निर्धारण करने के लिए उस राज्य के कराधान प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना अपर्याप्त हो, बशर्ते कि इस अनुच्छेद के सिद्धांतों के अनुसार, जहाँ तक व्यवहार्य हो, कानून लागू किया जाएगा।

(3) वे लाभ जिन पर किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उसी राज्य में कर प्रभाविता किया गया हो और जिनको पैराग्राफ (1) अथवा (2) के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभों में भी शामिल किया गया हो और उन पर उस दूसरे राज्य में कर प्रभाविता किया गया हो, और इस प्रकार शामिल किए गए लाभ वे लाभ होते जो दूसरे राज्य के उद्यम को तब प्राप्त हुए होते, यदि उद्यमों के बीच में लागू शर्तें वे होती जो कि एक दूसरे के साथ पूर्णतः संबंध रखने वाले स्वतंत्र उद्यमों के बीच में लागू होती हैं, तो उस अवस्था में प्रयोज्य राज्य, उन लाभों पर प्रयोज्य राज्य में प्रभाविता कर की राशि में उपर्युक्त समायोजन करेगा। ऐसे समायोजन का निर्धारण करते समय, इस करार के अन्य उपबंधों पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्य के सभ्य प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद--10

लाभांश

1. किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा अपने कर के प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश, जिसका कि वह हितभोगी स्वामी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में करावेय होंगे।

2. इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी करावेय होंगे जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी अपने कर के प्रयोजनों के

लिए और उस राज्य के कानून के अनुसार वहाँ की निवासी है, परन्तु इस प्रकार से प्रभावित कर की राशि उक्त लाभांशों की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद में, "लाभांश" शब्द का अर्थ है शेरों से भाग और अन्य भाग जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है जो कि उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के द्वारा शेरों से प्राप्त भाग के मामले में लागू होती है, जिसकी कि कर के प्रयोजनों के लिए वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी कम्पनी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभोगी व्यक्ति किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य के, जिसकी लाभांश भुगतान करने वाली कम्पनी निवासी हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ निष्पादित करता हो, और वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश भुगतान किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे किसी मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14, से जैसा भी मामला हो, के उपबन्ध लागू होंगे।

5. किसी एक संविदाकारी राज्य की किसी निवासी कम्पनी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान किए गए लाभांश जिनका हितभोगी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है, उसे दूसरे राज्य में कर से छूट होगी, के सिवाय उस सम्पत्ति के, जिसके संबंध में लाभांश दिया गया हो और जो दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। बशर्ते कि यह पैराग्राफ किसी ऐसी कम्पनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांशों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा, जो कि आस्ट्रेलियाई करों के प्रयोजनों के लिए आस्ट्रेलियाई की निवासी हो और भारतीय कर के प्रयोजनों के लिए भारत की निवासी हो।

अनुच्छेद—11

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाला व्याज, जिसका कि दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हितभोगी स्वामी है, पर दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानून के अनुसार भी कर लगेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है परन्तु इस प्रकार लगाया जाने वाला कर व्याज की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में "व्याज" शब्द में निम्नलिखित शामिल है सरकारी प्रतिभूतियाँ अथवा वंशपत्रों से अथवा ऋणपत्रों से व्याज, चाहे वे रेहन के आधार पर गारंटीयुक्त हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और किसी अन्य प्रकार की ऋणप्रस्तुता से प्राप्त व्याज और साथ ही उस संविदाकारी राज्य, जिसमें भाग उद्भूत होती है, के कर से संबंधित कानून द्वारा ऋण लेकर प्राप्त भाग से एकत्रित अन्य सभी प्रकार की भाग, परन्तु इसमें अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित व्याज शामिल नहीं है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज का हितभोगी स्वामी व्यक्ति, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें व्याज प्रोत्पन्न हुआ हो, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है, अथवा दूसरे राज्य में वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ प्रदान करता है, और वह ऋणप्रस्तुता जिसके

द्वारे में व्याज भुगतान किया गया हो, इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबन्ध लागू होंगे।

5. किसी संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में व्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा, जब व्याज भुगतान करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, अथवा कोई स्वतंत्र प्राधिकरण अथवा कोई व्यक्ति जो इसके कर के प्रयोजनों के लिए उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहाँ व्याज भुगतान करने वाला व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के बाहर एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान रखता है जिसके संबंध में वह ऋण दिया गया था, जिस पर व्याज की भुगतानी की जाती है, और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का व्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहाँ व्याज भुगतान करने वाला व्याज के हितभोगी स्वामी व्यक्ति के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अथवा की गई व्याज की राशि उस ऋण-प्रस्तुता को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए व्याज की राशि भुगतान की गई है उस राशि से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में भुगतान और इस प्रकार हकदार व्यक्ति के बीच सहमति हुई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित राशि पर लागू होंगे। उस मामले में भुगतान किए गए व्याज की राशि के प्रतिरिक्त भाग पर अन्त्येक संविदाकारी राज्य के कर से संबंधित कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार के अन्य उपबंधों का पालन किया जाता हो।

अनुच्छेद—12

रायल्टियाँ

(1) किसी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली रायल्टियाँ जिनका कि दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हितभोगी स्वामी है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

(2) ऐसी रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में, जिसमें वे उद्भूत होती हैं, और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगेगा परन्तु इस प्रकार लगाया गया कर इसमें अधिक नहीं होगा:

(क) निम्नलिखित के मामले में;

(i) उपपैराग्राफ (3) (ख) में निर्दिष्ट रायल्टियाँ;

(ii) उपपैराग्राफ (3) (ज) से (ड) के अध्याख्यान उपपैराग्राफ (3) (घ) में निर्दिष्ट सेवाओं के लिए भुगतानियाँ अथवा फीट, जो उस उपस्कर के अनुप्रयोग अथवा इस्तेमाल के लिए अनुषंगी और सहायक स्वरूप की होती हैं, जिनके लिए उपपैराग्राफ 3(ख) की अधीन अदायगियाँ अथवा फीट दिये जाते हैं, अथवा

(iii) उपपैराग्राफ 3 (च) में निर्दिष्ट रायल्टियाँ जो कि उपपैराग्राफ (3) (ख) में उल्लिखित उपस्कर से संबंधित हैं:

रायल्टियों की सकल राशि का 10 प्रतिशत; और

(ख) और अन्य रायल्टियों के मामले में:

(i) प्रथम 5 वर्षों के दौरान की वह भाग जिसके संबंध में यह करार किया गया है:

(क) जहाँ पर सरकार अथवा उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भुगतान करती हो: रायल्टियों की सकल राशि का 15 प्रतिशत; और

(ख) अन्य सभी मामलों में : रायल्टियों की सहाय राशि का 20 प्रतिशत : और

(ii) आय के सभी अनुवर्ती वर्षों के दौरान : रायल्टियों की सकल राशि का 15 प्रतिशत।

(3) इस अनुच्छेद में रायल्टियाँ शब्द का अर्थ है—अदायगियों अथवा क्रेडिट, चाहे प्राथमिक हों अथवा नहीं, और जो उस सीमा तक वर्णित अथवा संगणित हों जहाँ तक वे अदायगियों निम्नलिखित के लिए प्रतिकूल के रूप में की जाती हैं :

- (क) किसी कापीराइट, पेटेंट, डिजाइन अथवा नमूने, प्लान, गुप्त कार्गो अथवा प्रक्रिया, ड्रेडमार्क अथवा अन्य जसे सम्पत्ति अथवा अधिकार के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार;
- (ख) किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार;
- (ग) वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक जानकारी अथवा सूचना की आपूर्ति;
- (घ) तकनीकी अथवा परामर्शदात्री सेवाएँ (तकनीकी अथवा अन्य कार्मिक सेवाओं सहित) प्रदान करना जो कि किसी सम्पत्ति अथवा अधिकार के उपयोग अथवा इस्तेमाल के लिए अनुबंधी और सहायक हैं; जैसा कि उप-पैराग्राफ (क) में उल्लेख किया गया है, ऐसा कोई उपकरण जैसा कि उप-पैराग्राफ (ख) में उल्लेख किया गया है अथवा ऐसी कोई जानकारी अथवा सूचना जैसा कि उप-पैराग्राफ (ग) में उल्लिखित है;

(ड) निम्नलिखित का प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार :

- (i) चलचित्र फिल्मों;
- (ii) दूरदर्शन के उपयोग के लिए फिल्मों और वीडियो टेपें; अथवा
- (iii) रेडियो प्रसारण के संबंध में उपयोग के लिए टेपें;
- (च) उप-पैराग्राफ (क) से (ड) में उल्लिखित किसी सम्पत्ति अथवा अधिकार के उपयोग अथवा आपूर्ति के संबंध में पूर्ण अथवा आंशिक परिहार; अथवा

(छ) ऐसी सेवाएँ (तकनीकी अथवा अन्य कार्मिक सेवाओं सहित) प्रदान करना जो तकनीकी जानकारी, अनुभव, कौशल, विज्ञान प्रक्रिया उपलब्ध करवाती हों अथवा जिसमें किसी तकनीकी प्लान अथवा डिजाइन का विकास तथा अंतरण शामिल हों;

किन्तु उक्त पद में उप-पैराग्राफ (घ) और (छ) में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित अदायगियाँ अथवा क्रेडिट शामिल नहीं हैं जो कि निम्नलिखित के संबंध में दिये जाते हैं;

- (अ) वे सेवाएँ जो अनुबंधी और सहायक स्वरूप की हों, और दलचर्चीय रूप से और अनिवार्य रूप से सम्पत्ति की बिक्री से सम्बद्ध हों;
- (आ) वे सेवाएँ जो अन्तरराष्ट्रीय यातायात में अलयातों अथवा वायुयानों के संचालन में इस्तेमाल होने वाले जलयानों, वायुयानों, कन्टेनरों अथवा अन्य उपकरणों को किराये पर उठाने के लिए अनुबंधी और सहायक स्वरूप की हों;
- (इ) किसी वैश्विक संस्थान में अध्यापन अथवा शिक्षण के लिए;
- (ई) अदायगियाँ अथवा क्रेडिट देने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी प्रयोग के लिए सेवाएँ; अथवा
- (ठ) व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की किसी फर्म (कंपनी के अलावा) को अदायगियाँ अथवा क्रेडिट देने वाले व्यक्ति का कोई कर्मचारी जैसा कि अनुच्छेद 14 में परिभाषित है।

(4) पैरा 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियों का हितभोगी स्वामी व्यक्ति जो किसी एक संबिदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संबिदाकारी राज्य में, जिनमें रायल्टियाँ उद्भूत होती हैं, वहाँ पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहाँ पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ करता है और जिस सम्पत्ति के अधिकार अथवा सेवाओं के संबंध में रायल्टियाँ अदा की जाती हैं अथवा क्रेडिट की जाती हैं वे प्रभावी रूप से ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से संबंधित हैं। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

(5) एक संबिदाकारी राज्य में रायल्टियाँ तब उद्भूत हुईं मानी जाएंगी, जब रायल्टियाँ अदा करने वाला स्वयं राज्य अथवा उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई व्यक्ति जो कर के प्रयोजनों के लिए उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहाँ रायल्टियाँ अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संबिदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो। एक संबिदाकारी राज्य में अथवा दोनों संबिदाकारी राज्यों के बाहर उसका कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियाँ अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी रायल्टियाँ उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहुत की जाती हों, वहाँ पर ऐसी रायल्टियाँ उस संबिदाकारी राज्य में उद्भूत हुईं मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

(6) जहाँ रायल्टियों का अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी व्यक्ति के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई रायल्टियों की रकम, जिसके लिए इसकी अदायगी की गई थी, अथवा क्रेडिट की गई थी उस रकम से बहुत जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध सही होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितभोगी स्वामी व्यक्ति के बीच सहमति हो गई होगी, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। उस मामले में, अथवा की गई अथवा क्रेडिट की गई रायल्टियों के प्रतिरिक्त भाग पर, प्रत्येक संबिदाकारी राज्य के करों से संबंधित कानूनों के अनुसार कर लगाया जाता रहेगा ब्रजर्त कि इस प्रकार के अन्य उपायों का पालन किया जाता है।

अनुच्छेद—13

सम्पत्ति का अंतरण

1. किसी एक संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित, उस अनुच्छेद में की गई व्यवस्था के अनुसार, दूसरे संबिदाकारी राज्य में स्थित वास्तविक सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाली आय अथवा अभिलाषों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित वास्तविक सम्पत्ति से भिन्न किसी ऐसी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त हुई आय अथवा अभिलाषों पर, जो दोनों संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक संबिदाकारी राज्य के किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति के भाग के रूप में दूसरे संबिदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो दोनों संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक प्रथम वर्णित राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संबिदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान से संबंधित हो, जिसमें ऐसे किसी स्थायी संस्थापन (अथवा अथवा संपूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से प्राप्त होने वाली आय अथवा अभिलाष भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाने जाने वाले अलयातों अथवा वायुयानों के अंतरण से अथवा जैसे कि अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट है, से भिन्न

किसी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त आय अथवा अश्लेषाओं पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा जिसमें कि वह उद्यम, जिसने जनयानों और वायुयानों का संचालन किया था, स्थित है।

4. किसी एक संविदाकारी राज्य में उस कंपनी के शेयरों अथवा मुख्य हितों के अंतरण से प्राप्त आय अथवा अश्लेषाओं जिसकी परिसम्पत्तियों में अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट वास्तविक सम्पत्ति पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से शामिल है और जैसे कि उस अनुच्छेद में उपबंधित है, पर उस राज्य में कर लगेगा।

5. किसी कंपनी के शेयरों अथवा मुख्य हितों के अंतरण से प्राप्त आय तथा अश्लेषाओं पर जो पैराग्राफ (4) में निर्दिष्ट से भिन्न हों, उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जहाँ वह कंपनी स्थित है।

6. इस करार में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, उस संपत्ति को छोड़कर जिस पर पैराग्राफ (1), (2), (3), (4) और (5) लागू होते हैं किसी अन्य संपत्ति के अंतरण से प्राप्त पूंजीगत स्वरूप के धनसमाधियों के काराधान से संबंधित किसी संविदाकारी राज्य के किसी कानून को लागू करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

किसी व्यक्ति अथवा व्यष्टियों की फर्म (कंपनी के अलावा) जो कि किसी एक संविदाकारी राज्य में स्थित है उसके द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों से प्राप्त आय पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा यदि :

(क) व्यष्टि अथवा फर्म को अपने अथवा फर्म के कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध न हो, उन मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी ही आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान पर किए गए कार्यकलापों के कारण उत्पन्न हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अथवा किसी फर्म के मामले में, फर्म के एक या अधिक सदस्यों द्वारा (अकेले अथवा मिलकर) दूसरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की प्रवृत्ति अथवा अवधि या आय वाले वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा इससे अधिक न हो तो उन मामले में, उतनी ही आय पर जो यथास्थिति उस व्यक्ति, उस सदस्य अथवा उन सदस्यों के कार्यकलापों से उस दूसरे राज्य में प्राप्त हुई हो, उग दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद के अर्थ विस्तार के अन्तर्गत वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी स्वतंत्र कार्यकलापों का निष्पादन तथा चिकित्सकों, शल्य चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुशिल्पियों, दंत चिकित्सकों तथा लेखापालों, द्वारा निष्पादित स्वतंत्र स्वरूप के कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंधों के अन्तर्गत रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी

है किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, यात्रा तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि इन प्रकार का नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वही से प्राप्त होता है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ (1) के उपबंधों के होते हुए भी, किसी व्यक्ति द्वारा जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रयोजित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता आय वाले वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की प्रवृत्ति अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो ;

(ख) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रदा किया जाता है, जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान के काराधेय लाभों का निर्धारण करते समय काटा नहीं जाता हो, जो नियोजक के दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्व के उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में किसी जलयान अथवा वायुयान पर सवार होकर उसके परिचालन में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 16

निदेशकों की फीस

किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी कंपनी के निदेशक मण्डल के एक सदस्य के रूप में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, प्राप्त निदेशक की फीस और अन्य समरूप अदायगियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद 17

मनोरंजनकर्ता

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी एक संविदाकारी राज्य के निवासियों द्वारा मनोरंजनकर्ताओं के रूप में जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकारों, संगीतकारों और खिलाड़ियों के रूप में, दूसरे संविदाकारी राज्य में इस प्रकार सम्पन्न किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों से उत्पन्न आय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता को प्रभावित नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है, तो अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता ने कार्यकलाप सम्पन्न किए हैं।

3. पैराग्राफ (1) के उल्लेखों के होते हुए भी किसी मनोरंजन कर्मी द्वारा, जो एक सविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में उसी हैमियत से किए गए मनोरंजनकर्ता के व्यक्तिगत कार्यक्रमों से अर्जित आय प्रथमोलिखित सविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी यदि दूसरे सविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से प्रथमोलिखित सविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधि तथा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समर्थित हों।

4. पैराग्राफ (2) तथा अनुच्छेद 7, 14 तथा 15 के उपबन्धों के होते हुए भी, जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता द्वारा मनोरंजनकर्ता की हैमियत से किसी सविदाकारी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता को प्राप्त नहीं होती है अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह आय केवल दूसरे सविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी यदि वह दूसरा व्यक्ति उस दूसरे राज्य की सार्वजनिक निधि तथा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित हो।

अनुच्छेद 18

पेंशन और वापिसी

1. सविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी को प्रदान पेंशन (अनुच्छेद 19 में निविष्ट पेंशनों को छोड़कर) और वापिसियों पर केवल उस राज्य में कर लगेगा।

2. "वापिसी" शब्द का अर्थ उस उल्लिखित राशि से है जो वन अथवा घन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिकूल के लिए, अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन, जीवन पर्याप्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर सामयिक रूप से देय हो।

अनुच्छेद 19

सरकारी सेवा

1. सविदाकारी राज्यों में से एक राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उस राज्य के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को, सरकारी कार्यक्रमों के निर्वहन के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में अथवा की गई पेंशन अथवा वापिसी से भिन्न पारिश्रमिक की राशि केवल उसी राज्य में कराधेय होगी। तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस दूसरे सविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और प्राप्तकर्ता उस दूसरे राज्य का निवासी हो जो :

(क) उस राज्य का राष्ट्रिक हो; अथवा

(ख) मात्र सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. सविदाकारी राज्यों में से एक राज्य अथवा उसके एक राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई

सेवाओं के संबंध में उस राज्य अथवा उपप्रभाग अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को अदा की गयी अथवा उनके द्वारा सुजित की गयी निधियों में से अथवा की गयी पेंशन पर उसी राज्य में कर लग सकेगा तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे सविदाकारी राज्य में लेवल नहीं कर लग सकेगा यदि वह प्राप्तकर्ता उस दूसरे राज्य का निवासी और नागरिक हो।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपबंध परिस्थितियों के अनुसार यथोचित रूप से, एक सविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए कारबार के संबंध में प्रदान की गयी सेवाओं के सिपविले में प्राप्त पारिश्रमिक और पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 20

प्राध्यापक और अध्यापक

1. यदि सविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का कोई निवासी प्राध्यापक अथवा अध्यापक दो वर्ष से अनाधिक अर्थात् के लिए दूसरे सविदाकारी राज्य की यात्रा पर किसी विश्वविद्यालय, कलेज, स्कूल अथवा अन्य शैक्षिक संस्थान में अध्यापन अथवा उच्च अध्ययन अथवा अनुसंधान कार्य के प्रयोजनार्थ जाता है और यदि वह व्यक्ति ऐसे अध्यापन, उच्च अध्ययन अथवा अनुसंधान के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो उस पर उस दूसरे राज्य में कर के उस सीमा तक छूट मिलेगी जिन सीमा तक ऐसे पारिश्रमिक पर, अथवा इस अनुच्छेद की लागू करने पर, प्रथमोलिखित राज्य में कर लगेगा।

2. यह अनुच्छेद किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को जोध कार्य से प्राप्त पारिश्रमिक पर उस स्थिति में लागू नहीं होगा, यदि अनुसंधान मुख्यतः किसी विनिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाना है।

अनुच्छेद 21

छात्र और प्रशिक्षु

यदि कोई छात्र अथवा प्रशिक्षु जो सविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का निवासी है अथवा दूसरे सविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुरन्त पहले उस राज्य का निवासी था, और जो मात्र अपनी अथवा प्रशिक्षु की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन उस दूसरे राज्य में अम्पाई रूप से उपस्थित है तथा उसे अपने अथवा प्रशिक्षु के भरण पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य से बाहर के स्रोतों से अदायगियां प्राप्त होती हैं, तो उन अदायगियों पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट मिलेगी।

अनुच्छेद 22

आय जिसका स्पष्टतः उल्लेख नहीं है

1. सविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी की आय की उन भदों पर, जिनका इस प्रकार के पूर्ववर्ती अनुच्छेद में स्पष्टतः उल्लेख नहीं है, केवल उस राज्य में ही कर लगेगा।

2. तथापि, संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्रोतों से व्युत्पन्न किसी ऐसी आय पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

3. पैरा (1) के उपबंध, संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी द्वारा व्युत्पन्न आय पर उग स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि वह आय दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थाई संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे किसी मामले में, यथामिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

अनुच्छेद 23

आय का स्रोत

1. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी द्वारा व्युत्पन्न आय, लाभ अथवा अनुलाभ, जिन पर अनुच्छेद 6 से 8, अनुच्छेद 10 से 20 और अनुच्छेद 22 में से किसी एक अथवा एक से अधिक के तहत दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, उन्हें उस दूसरे राज्य के कर से संबंधित कानून के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में समझा जाएगा।

2. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी द्वारा व्युत्पन्न आय, लाभ अथवा अनुलाभ, जिन पर अनुच्छेद 6 से 8, अनुच्छेद 10 से 20 और अनुच्छेद 22 में से एक अथवा एक से अधिक के तहत दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, उन्हें अनुच्छेद 24 तथा प्रथमोल्लिखित राज्य के कर से संबंधित कानून के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में समझा जाएगा।

अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान के अपाकरण के तरीके

1. (क) आस्ट्रेलिया से बाहर के किसी देश में प्रदत्त आस्ट्रेलियाई कर के प्रति क्रेडिट की अनुमति से संबंधित समय-समय पर प्रवृत्त आस्ट्रेलियाई कानून के उपबंधों के अधधीन (जो इसके सामान्य मिश्रणों को प्रभावित नहीं करेंगे) आस्ट्रेलिया के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में स्रोतों से व्युत्पन्न आय के संबंध में, भारतीय कानून के अंतर्गत और इस करार के अनुसार प्रदत्त भारतीय कर, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती द्वारा प्रदा किया गया हो, को उस आय के संबंध में संदेय आस्ट्रेलियाई कर के प्रति क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी।

(ख) जहाँ कोई कंपनी, जो भारत की निवासी कंपनी है और आस्ट्रेलियाई कर के प्रयोजनों के लिए आस्ट्रेलिया की निवासी नहीं है, यदि वह किसी ऐसी कंपनी को लाभांश देती है जो आस्ट्रेलिया की निवासी कंपनी है और जो प्रथमोल्लिखित कंपनी के सहाधिकार शक्ति के कम से कम 10 प्रतिशत भाग पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है, तो उस स्थिति में उप पैरा (क) में निर्दिष्ट क्रेडिट में उस प्रथमोल्लिखित कंपनी के लाभ के उस भाग के संबंध में उसके द्वारा प्रदत्त भारतीय कर शामिल होगा जिसमें से लाभांश दिया गया हो।

2. पैरा (1) में, अथवा किए गए भारतीय कर में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) उप पैरा (ख) के अधधीन, भारतीय कर में संबंधित भारतीय कानून के तहत और इस प्रकार के अनुसार, भाग की गई भारतीय कर की किसी रकम के बराबर की राशि, आय पर भारतीय कर के रूप में संदेय हो गयी होती यदि निम्नलिखित के अनुसार उस आय पर भारतीय कर से कोई छूट अथवा उममें कोई कटौती नहीं की गई होती :

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (4), 10 (15) (iv), 10क, 10ख, 80जअ, 80जब अथवा 80म, जहाँ तक उनके उपबंध इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को प्रवृत्त थे और जिन्हें तब से संशोधित नहीं किया गया है अथवा उनमें केवल मामूली से संशोधित किए गए हैं ताकि उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव न पड़े; अथवा

(ii) अन्य कोई उपबंध, जिसे तदनन्तर भारतीय कर से छूट देने अथवा उममें कटौती करने के लिए बनाया जाए, जिसके लिए आस्ट्रेलिया का वित्त मंत्रालय और भारत का वित्त मंत्रालय इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर पत्रों के आदान-प्रदान के जरिये सहमत हों और उसका मुख्य स्वरूप बही बना रहे, यदि उस उपबंध को उसके बाद संशोधित नहीं किया गया है अथवा उसमें केवल मामूली से संशोधित किया गया है ताकि उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े; और

(ख) आस्ट्रेलिया के किसी निवासी के द्वारा व्युत्पन्न व्याज के उग मामले में, जिस पर उप पैरा (क) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधधीन भारतीय कर से छूट प्राप्त है, वह रकम जो भारतीय कर के रूप में संदेय हो जाती यदि व्याज पर इस प्रकार की छूट नहीं दी जाती और यदि अनुच्छेद 11 के पैरा (2) में निर्दिष्ट कर सकल व्याज के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता।

3. पैरा (2) केवल प्रथम 10 वर्षों के किसी वर्ष में व्युत्पन्न आय के संबंध में ही लागू होगा जिसके बारे में इस करार के अनुच्छेद 28 का उप पैरा (1)(क)(ii) लागू होता है अथवा बाद के किसी वर्ष की आय, जिसके संबंध में इस प्रयोजनार्थ पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा संविदाकारी राज्यों में सहमति हुई हो।

4. भारत के मामले में, दोहरे कराधान का परिहार निम्नलिखित रूप से किया जाएगा :

(क) आस्ट्रेलिया के कानूनों के तहत और इस करार के उपबंधों के अनुसार आस्ट्रेलिया में स्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में भारत के किसी निवासी द्वारा प्रदत्त कर की रकम, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा की गई हो अथवा कटौती के रूप में अथवा की गई हो, जिस पर भारत तथा आस्ट्रेलिया, दोनों देशों में कर लगाया गया हो, उस पर ऐसी आय के संबंध में

संघेय भारतीय कर के प्रति क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी किन्तु यह राजि भारतीय कर की उय रकम के अनुपात से अधिक नहीं हो जो ऐसी आय के मिलाने में भारतीय कर के अनुसार प्रभाय समस्त आय पर प्रदत्त हो ; और

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) में निर्दिष्ट क्रेडिट के प्रयोजनों के लिए, यदि कोई कंपनी भारत की निवासी है जिसके द्वारा अतिकर संघेय है, तो भारतीय कर के प्रति दिया जाने वाला क्रेडिट, भारत में उस कंपनी द्वारा संघेय आयकर के प्रति पहली बार अनुमोद पर दिया जाएगा और, यदि कुछ शेष रह जाए तो वह भारत में उसके द्वारा संघेय अतिकर के प्रति दिया जाएगा।

5. यदि संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का कोई निवासी इस करार के उपबन्धों के अनुसार ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगेगा, तो प्रथमोलिखित राज्य उस निवासी की बाकी आय पर संघेय अपने कर की रकम को परिकल्पित करने में उस आय को हिसाब में ले सकता है।

अनुच्छेद 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. यदि संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कराधान प्राधिकारी की कार्यवाहियों के परिणामतः उस व्यक्ति पर इस करार के उपबन्धों के अनुसार कर नहीं लगाया जाता है अथवा नहीं लगाया जाएगा, तो वह व्यक्ति उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबन्धित उपायों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। यह मामला कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण वह कर लगाया गया है जो इस करार के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को यह दावा उचित लगे और यदि वह किसी समुचित हल पर पहुँचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से जो इस करार के अन्तर्गत नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार जो हल निकलेगा उसे कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो।

3. इस करार को लागू करने में यदि कोई कठिनाईयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें संयुक्त रूप से हल करने का प्रयास करेंगे।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के उपबन्धों को लागू करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं।

अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है जिन पर यह करार लागू होता है, जहां तक कि उनके अधीन की गयी कराधान व्यवस्था, अथवा करों के अपवर्जन अथवा परिहार, अथवा ऐसे करों से संबंधित जालमाजी को रोकने के लिए की गई व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं हो। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद-1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और इसे ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट किया जाएगा जो उन करों के निर्धारण अथवा उगाहो, उनके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हों, जिन पर यह करार लागू होता है और उसका इस्तेमाल केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा वे इस सूचना को सार्वजनिक नीति पर न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. सक्षम प्राधिकारी परामर्श करके उन मामलों से संबंधित समुचित जर्नाल, तरीकों और तकनीकों को विकसित कर सकते हैं जिनके संबंध में ऐसी सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा। सूचना का आदान-प्रदान मामलों विशेष के संदर्भ में सामान्य रूप से होगा अथवा अनुरोध करने पर, अथवा दोनों तरह से। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सूचना की उग सूची पर समय-समय पर सहमत हो सकते हैं जिसे सामान्य तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैरा 1 के उपबन्धों का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वे एक संविदाकारी राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी को निम्न-लिखित के लिए बाध्य करते हैं:—

(क) ऐसे प्रशासनिक उपाय करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से भिन्न हों;

(ख) ऐसी सूचना देना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रणामन की सामान्य स्थिति में प्राप्त करने योग्य नहीं हों;

(ग) ऐसी सूचना देना, जिससे कोई व्यापारिक व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्ति संबंधी गुप्त श्रेय अथवा व्यापारिक प्रक्रिया प्रकट होती हो अथवा ऐसी सूचना देना जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद—27

राजनयिक और कौमुदी अधिकारी

इस करार की किमती भीज्ञान में राजनयिक अथवा कौमुदी अधिकारियों के उन वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उन्हें अन्तर्राष्ट्रीयविधि के सामान्य दिवसों के अन्तर्गत अथवा विशेष अन्तर्राष्ट्रीय करारों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त है।

अनुच्छेद—28

प्रवर्तन

1. यह करार उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको संविधाकारी राज्य राजनयिक माध्यम से एक-दूसरे को इस बारे में सूचित करते हुए टिप्पणियों का आदान-प्रदान करें कि यथा-स्थिति, आस्ट्रेलिया में और भारत में इस करार को लागू करने के लिए यथा आवश्यक अन्तिम औपचारिकता पूरी हो चुकी हों, और तदन्तर इस करार का यह प्रभाव होगा:

(क) आस्ट्रेलिया में:

(i) किसी गैर-निवासी द्वारा व्युत्पन्न आय पर प्रवधारण कर के संबंध में, जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार प्रवृत्त होता है उसके बाद के परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में एक जुलाई को अथवा उसके पश्चात् व्युत्पन्न आय के संबंध में; और

(ii) अन्य आस्ट्रेलियाई कर के संबंध में, जिस कैलेण्डर वर्ष से यह करार प्रवृत्त होता है उसके बाद के परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में एक जुलाई को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी आय-वर्ष की आय, लाभों अथवा अनुलाभों के संबंध में;

(ख) भारत में:

जिस कैलेण्डर वर्ष से यह करार प्रवृत्त होता है उसके बाद के परवर्ती वर्ष में एक अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी आय-वर्ष में उद्भूत आय, लाभों अथवा अनुलाभों के संबंध में।

2. आस्ट्रेलिया सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच 31 मई, 1983 को कैनबरा में हस्ताक्षरित अन्तरराष्ट्रीय वायु परिवहन से व्युत्पन्न आय के दोहरे कराधान के परिहार के लिए किए गए करार (जिसे हम अनुच्छेद में "1983 का करार" कहा गया है) का प्रभाव उन करों के संबंध में, जिन पर यह करार लागू होना है, उस समय समाप्त हो जाएगा जब इस करार के उपबंध पैरा (1) के अनुसार प्रभावी बन जाएंगे।

3. 1983 का करार उस अन्तिम तारीख की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा जिसको इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार यह प्रभावी होगा।

अनुच्छेद—29

पर्याप्तमान

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा, किन्तु दोनों में से कोई भी संविधाकारी राज्य, इस करार के प्रवृत्त होने की तारीख से 5 वर्ष की

समाप्ति के पश्चात् होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष में 30 जून को अथवा उससे पहले, दूसरे संविधाकारी राज्य को राजनयिक माध्यम से पर्याप्तमान संबंधी लिखित नोटिस दे सकता है और उस दशा में इस करार का प्रभाव इस प्रकार समाप्त हो जाएगा:

(क) आस्ट्रेलिया में:

(i) किसी गैर-निवासी द्वारा व्युत्पन्न आय पर प्रवधारण कर के संबंध में, जिस कैलेण्डर वर्ष में पर्याप्तमान का नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती वर्ष में एक जुलाई को अथवा उसके बाद व्युत्पन्न आय के संबंध में; और

(ii) अन्य आस्ट्रेलिया कर के संबंध में, जिस कैलेण्डर वर्ष में पर्याप्तमान का नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में एक जुलाई को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी आय-वर्ष की आय, लाभों अथवा अनुलाभों के संबंध में;

(ख) भारत में:

जिस कैलेण्डर वर्ष में पर्याप्तमान का नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में एक अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी आय-वर्ष में उद्भूत होने वाली आय, लाभों अथवा अनुलाभों के संबंध में।

जिसके माध्यम से, इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अंगरक्षकधारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

कैनबरा में वर्ष एक हजार नौ सौ इस्त्रानवे के जुलाई माह के पञ्चमिषे दिन को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतिभों में बनाया गया, जिनके दोनों पाठ समतल: प्रामाणिक होंगे। इन दो पाठों के बीच भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

आस्ट्रेलिया सरकार
की ओर से

[अधिसूचना सं. 8984 (फा. सं. 501/1/79-एफ. टी. जी.)]

एन. सी. जैंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

FOREIGN TAX DIVISION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1992

(INCOME TAX)

G.S.R. 60(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Australia for the avoidance of

double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on the 30th day of December, 1991, on the exchange of notes notifying each other that the last of such things has been done as is necessary to give the said Agreement the force of law in India and in Australia, in accordance with paragraph (1) of Article 28 of the said Agreement :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

AND

THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of Australia,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

ARTICLE 1

Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

TAXES COVERED

(1) The existing taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) in Australia :

the income tax, and the resource rent tax in respect of offshore projects relating to exploration for or exploitation of petroleum

resources, imposed under the federal law of the Commonwealth of Australia;

(b) in India :

(i) the income tax including any surcharge thereon; and

(ii) the surtax imposed on chargeable profits of companies.

(2) This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed under the federal law of the Commonwealth of Australia or the law of the Republic of India after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in the laws of their respective States relating to the taxes to which this Agreement applies.

ARTICLE 3

General Definitions

(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires :

(a) the term "Australia", when used in a geographical sense, excludes all external territories other than :

(i) the Territory of Norfolk Island;

(ii) the Territory of Christmas Island;

(iii) the Territory of Cocos (Keeling) Islands;

(iv) the Territory of Ashmore and Cartier Islands;

(v) the Territory of Heard Island and McDonald Islands; and

(vi) the Coral Sea Islands Territory,

and includes any area adjacent to the territorial limits of Australia (including the Territories specified in sub-paragraphs (i) to (vi) inclusive, in respect of which there is for the time being in force, consistently with international law, a law of Australia dealing with the exploitation of any of the natural resources of the seabed and subsoil of the continental shelf; }

(b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and the air space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions,

according to the Indian law and in accordance with international law;

- (c) the terms "Contracting State", "one of the Contracting States" and "other Contracting State" mean, as the context requires, Australia or India, the Governments of which have concluded this Agreement;
- (d) the term "person" includes an individual, a company, any other body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit for tax purposes;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate for tax purposes;
- (f) the term "enterprise of one of the Contracting States" and "enterprise of the other Contracting State" mean an enterprise carried on by a resident of Australia or an enterprise carried on by a resident of India, as the context requires;
- (g) the term "tax" means Australian tax or Indian tax, as the context requires;
- (h) the term :
 - (i) "Australian tax" means tax imposed by Australia; and
 - (ii) "Indian tax" means tax imposed by India, being tax to which this Agreement applies by virtue of Article 2, but neither term includes any amount which represents a penalty or fine or interest imposed under the law of either Contracting State relating to its tax;
- (i) the term "competent authority" means, in the case of Australia, the Commissioner of Taxation or an authorised representative of the Commissioner and, in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and
- (j) the term "year of income", in relation to Indian tax, means "previous year" as defined in the Income-tax Act, 1961.

(2) In the application of this Agreement by a Contracting State, any term not defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State from time to time in force relating to the taxes to which this Agreement applies.

ARTICLE 4

Residence

(1) For the purposes of this Agreement, a person is a resident of one of the Contracting States if the person is a resident of that Contracting State for the purposes of its tax. However, a person is not a resident of a Contracting State for the purposes of this Agreement if the person is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

(2) Where, by reason of the provisions of paragraph (1), an individual is a resident of both Contracting States, then the status of that person shall be determined in accordance with the following rules :

- (a) the person shall be deemed to be a resident solely of the Contracting State in which a permanent home is available to the person ;
- (b) if a permanent home is available to the person in both Contracting States, or in neither of them, the person shall be deemed to be a resident solely of the Contracting State with which the person's personal and economic relations are closer (centre of vital interests).

For the purposes of this paragraph, an individual's citizenship of a Contracting State as well as that person's habitual abode shall be factors in determining the degree of the person's personal and economic relations with that Contracting State.

(3) Where, by reason of the provisions of paragraph (1), a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident solely of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

Permanent Establishment

(1) For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources ;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a farm, plantation or other place where agricultural, pastoral, forestry or plantation activities are carried on;
- (i) premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
- (j) an installation or structure, or plant or equipment, used for the exploration for or exploitation of natural resources;
- (k) a building site or construction, installation or assembly project, or supervisory activities in connection with such a site or project, where that site or project exists or those activities are carried on

(whether separately or together with other sites, projects or activities) for more than 6 months.

(3) An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in one of the Contracting States and to carry on business through that permanent establishment if :

- (a) substantial equipment is being used in that State by, for or under contract with the enterprise;
- (b) it carries on activities in that State in connection with the exploration for or exploitation of natural resources in that State; or
- (c) it furnishes services, including managerial services and those mentioned in subparagraphs (3)(h) to (k) of Article 12 but not those services in respect of which payments or credits that are royalties as defined in Article 12 are made, within one of the Contracting States through employees of other personnel, but only if those services are furnished within that State :
- (i) for a period or periods aggregating more than 90 days within any 12 month period; or
- (ii) for another enterprise if both enterprises are within either of the relationships described in subparagraphs (1)(a) and (b) of Article 9.

(4) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment merely by reason of :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise; or
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

However, the preceding provisions of this paragraph shall not apply where an enterprise of one of the Contracting States maintains in the other Contracting State a fixed place of business for any purpose other than those specified in this paragraph.

(5) A person acting in one of the Contracting States on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies—shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first mentioned State if :

- (a) the person has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless the person's activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;
- (b) the person has no such authority, but habitually maintains in that State a stock of goods or merchandise from which the person regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise;
- (c) the person habitually secures orders in that State, wholly or principally for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, or controlled by or subject to the same common control as, that enterprise; or
- (d) in so acting, the person manufactures or processes in that State for the enterprise goods or merchandise belonging to the enterprise.

(6) An enterprise of one of the Contracting States shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where that person is acting in the ordinary course of the person's business as such a broker or agent. However, when the activities of such a broker or agent are carried on wholly or principally on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, or controlled by or subject to the same common control as, that enterprises, the person will not be considered a broker or agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

(7) That fact that a company which is a resident of one of the Contracting States controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself make either company a permanent establishment of the other.

(8) The principles set forth in the preceding paragraphs of this Article shall be applied in determining for the purposes of paragraph (5) of Article 11 and paragraph (5) of Article 12 of this Agreement whether there is a permanent establishment outside both Contracting States, and whether an enterprise, not being an enterprise of one of the Contracting States, has a permanent establishment in one of the Contracting States.

ARTICLE 6

Income from Real Property (Immovable Property)

(1) Income from real property may be taxed in the Contracting State in which that property is situated.

(2) For the purposes of this Article, the term "real property":

- (a) in the case of Australia, has the meaning which it has under the laws of Australia and shall include:
 - (i) a lease of land and any other interest in or over land, whether improved or not; and
 - (ii) a right to receive variable or fixed payments either as consideration for the working of or the right to work or explore for, or in respect of the exploitation of, mineral or other deposits, oil or gas wells, quarries or other places of extraction or exploitation of natural resources; and
- (b) in the case of India, means such property which, according to the laws of India, is immovable property and shall include :
 - (i) property accessory to immovable property;
 - (ii) rights to which the provision of the general law respecting landed property apply; and
 - (iii) usufruct of immovable property and rights to receive variable or fixed payments either as consideration for the working of or the right to work or explore for, or in respect of exploitation of, mineral or other deposits, oil or gas wells, quarries or other places of extraction or exploitation of natural resources.

(3) A lease of land, any other interest in or over land and any rights or property referred to in any of the sub-paragraphs of paragraph (2) shall be regarded as situated where the land, mineral or other deposits, oil or gas wells, quarries, natural resources or property, as the case may be, are situated or where the exploration may take place.

(4) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of real property.

(5) The provisions of paragraphs (1), (3) and (4) shall also apply to the income from real property of an enterprise and to income from real property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

Business Profits

(1) The profits of an enterprise of one of the Contracting States shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to:

- (a) that permanent establishment; or
- (b) sales within that other Contracting State of goods or merchandise of the same or a similar kind as those sold, or other business activities of the same or a similar kind as those carried on, through that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of one of the Contracting States carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment or with other enterprises with which it deals.

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions, in accordance with and subject to the limitations of the law relating to tax in the Contracting State in which the permanent establishment is situated, expenses of the enterprise, being expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment (including executive and general administrative expenses so incurred), whether incurred in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

(4) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(5) Where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination by the taxation authority of one of the Contracting States or the ascertaining thereof by that authority presents exceptional difficulties, nothing in this Article shall affect the application of any law of that State relating to the determination of the tax liability of a person, provided that the law shall be applied, so far as the information available to that authority permits, in accordance with the principles of this Article.

(6) For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

(8) Nothing in this Article shall affect the operation of any law of a Contracting State relating to tax imposed on profits from insurance with non-residents provided that if the relevant law in force in either Contracting State at the date of signature of this Agreement is varied (otherwise than in minor respects so as not to affect its general character) the Contracting States shall consult with each other with a view to agreeing to any amendment of this paragraph that may be appropriate.

(9) Where :

- (a) a resident of one of the Contracting States is beneficially entitled, whether directly or through one or more interposed trust estates, to a share of the business profits of an enterprise carried on in the other Contracting State by the trustee of a trust estate other than a trust estate which is treated in that other State as a company for tax purposes; and
- (b) in relation to that enterprise, that trustee would, in accordance with the principles of Article 5, have a permanent establishment in that other Contracting State,

the enterprise carried on by the trustee shall be deemed to be a business carried on in that other Contracting State by that resident through a permanent establishment situated therein and that share of business profits shall be attributed to that permanent establishment.

ARTICLE 8

Ships and Aircraft

(1) Profits from the operation of ships or aircraft, including interest on funds connected with that operation, derived by a resident of one of the Contracting States shall be taxable only in that State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), such profits may be taxed in the other Contracting State where they are profits from the operations of ships or aircraft confined solely to places in that other State.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall apply in relation to the share of the profits from the operation of ships or aircraft derived by a resident of one of the Contracting States through participation in a pool service, in a joint transport operating organisation or in an international operating agency.

(4) For the purposes of this Article, profits derived from the carriage by ships or aircraft of passengers, livestock, mail, goods or merchandise shipped in a Contracting State for discharge at another place in that State shall be treated as profits from operations of ships or aircraft confined solely to places in that State.

ARTICLE 9

Associated Enterprises

(1) Where :

- (a) an enterprise of one of the Contracting States participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the Contracting States and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions operate between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which might be expected to operate between independent enterprises dealing wholly independently with one another, then any profits which, but for those conditions, might have been expected to accrue to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of the tax liability of a person, including determinations in cases where the information available to the taxation authority of that State is inadequate to determine the income to be attributed to an enterprise, provided that that law shall be applied, so far as it is practicable to do so, consistently with the principles of this Article.

(3) Where profits on which an enterprise of one of the Contracting States have been charged to tax in that State are also included, by virtue of paragraph (1) or (2), in the profits of an enterprise of the other Contracting State and charged to tax in that other State, and the profits so included are profits which might have been expected to have accrued to that enterprise of the other State if the conditions operative between the enterprises had been those which might have been expected to have operated between independent enterprises dealing wholly independently with one another, then the first-mentioned State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged on those profits in the first-mentioned State. In determining such an adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and for this purpose the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

ARTICLE 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of one of the Contracting States for the purposes of its tax, being dividends to which a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, may be taxed in that other State.

(2) Such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident for the purposes of its tax, and according to the law of that State, but the tax so

charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

(3) The term "dividends" in this Article means income from shares and other income which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident for the purposes of its tax.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the person beneficially entitled to the dividends, being a resident of one of the Contracting States, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In any such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Dividends paid by a company which is a resident of one of the Contracting States, being dividends to which a person who is not a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, shall be exempt from tax in that other State except insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or fixed base situated in that other State. Provided that this paragraph shall not apply in relation to dividends paid by any company which is a resident of Australia for the purposes of Australian tax and which is also a resident of India for the purposes of Indian tax.

ARTICLE 11

Interest

(1) Interest arising in one of the Contracting States, being interest to which a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, may be taxed in that other State.

(2) Such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

(3) The term "interest" in this Article includes interest from Government securities or from bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and interest from any other form of indebtedness as well as all other income assimilated to income from money lent by the law, relating to tax, of the Contracting State in which the income arises, but does not include interest referred to in paragraph (1) of Article 8.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the person beneficially entitled to the interest, being a resident of one of the Contracting States, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the indebtedness in respect of which

the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself or a political sub-division or local authority of that State or a person who is a resident of that State for the purposes of its tax. Where, however, the person paying the interest, whether the person is a resident of one of the Contracting States or not, has in one of the Contracting States or outside both Contracting States a permanent establishment or fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where, owing to a special relationship between the payer and the person beneficially entitled to the interest, or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the indebtedness for which it is paid, exceeds the amount which might have been expected to have been agreed upon by the payer and the person so entitled in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the amount of the interest paid shall remain taxable according to the law, relating to tax, of each Contracting State, but subject to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12

Royalties

(1) Royalties arising in one of the Contracting States, being royalties to which a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, may be taxed in that other State.

(2) Such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed :

(a) in the case of :

(i) royalties referred to in sub-paragraph (3) (b);

(ii) payments or credits for services referred to in sub-paragraph (3)(d), subject to sub-paragraphs (3) (h) to (l), that are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of equipment for which payments or credits are made under sub-paragraph (3) (b); or

(iii) royalties referred to in sub-paragraph (3) (f) that relate to equipment mentioned in sub-paragraph (3) (b);

10 per cent of the gross amount of the royalties; and

(b) in the case of other royalties :

(i) during the first 5 years of income for which this Agreement has effect :

(A) where the payer is the Government or a political sub-division of that State or a public sector company : 15 per cent of the gross amount of the royalties; and

(B) in all other cases : 20 per cent of the gross amount of the royalties; and

(ii) during all subsequent years of income : 15 per cent of the gross amount of the royalties.

(3) The term "royalties" in this Article means payments or credits, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for :

- (a) the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark, or other like property or right;
- (b) the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment;
- (c) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information;
- (d) the rendering of any technical or consultancy services (including those of technical or other personnel) which are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of any such property or right as is mentioned in sub-paragraph (a), any such equipment as is mentioned in sub-paragraph (b) or any such knowledge or information as is mentioned in sub-paragraph (c);
- (e) the use of, or the right to use:
 - (i) motion picture films;
 - (ii) films or video tapes for use in connection with television; or
 - (iii) tapes for use in connection with radio broadcasting;
- (f) total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property or right referred to in sub-paragraphs (a) to (e); or
- (g) the rendering of any services (including those of technical or other personnel) which make available technical knowledge, experience, skill, know-how or processes or consist of the development and transfer of a technical plan or design;

but that term does not include payments or credits relating to services mentioned in sub-paragraphs (d) and (g) that are made:

- (h) for services that are ancillary and subsidiary and inextricably and essentially linked, to a sale of property;

(i) for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic;

(j) for teaching in or by an educational institution;

(k) for services for the personal use of the individual or individuals making the payments or credits; or

(l) to an employee of the person making the payments or credits or to any individual or firm of individuals (other than a company) for professional services as defined in Article 14.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the person beneficially entitled to the royalties, being a resident of one of the Contracting States, carries on business in the other Contracting States, in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the property, right or services in respect of which the royalties are paid or credited are effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself or a political subdivision or local authority of that State or a person who is a resident of that State for the purposes of its tax. Where, however, the person paying the royalties, whether the person is a resident of one of the Contracting States or not, has in one of the Contracting States or outside both Contracting States a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred and the royalties are borne by the permanent establishment or fixed base, then the royalties shall be deemed to arise in the State in, which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where, owing to a special relationship between the payer and the person beneficially entitled to the royalties, or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid or credited, having regard to what they are paid or credited for, exceeds the amount which might have been expected to have been agreed upon by the payer and the person so entitled in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the amount of the royalties paid or credited shall remain taxable according to the law, relating to tax, of each Contracting State, but subject to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13

Alienation of Property

(1) Income or gains derived by a resident of one of the Contracting States from the alienation of real property referred to in Article 6 and, as provided in

that Article, situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Income or gains derived from the alienation of property. Other than real property referred to in Article 6, that forms part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of one of the Contracting States has in the other Contracting State or pertains to a fixed base available to a resident of the firstmentioned State in that other State for the purpose of performing independent personal services, including income or gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

(3) Income or gains derived from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or of property other than real property referred to in Article 6 pertaining to the operation of those ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise which operated those ships or aircraft is a resident.

(4) Income or gains derived from the alienation of shares or comparable interests in a company, the assets of which consist wholly or principally of real property referred to in Article 6 and, as provided in that Article, situated in one of the Contracting States, may be taxed in that State.

(5) Income or gains derived from the alienation of shares or comparable interests in a company, other than those referred to in paragraph (4), may be taxed in the Contracting State of which the company is a resident.

(6) Nothing in this Agreement affects the application of a law of a Contracting State relating to the taxation of gains of a capital nature derived from the alienation of property other than that to which any of paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) apply.

ARTICLE 14

Independent Personal Services

(1) Income derived by an individual or a firm of individuals (other than a company) who is a resident of one of the Contracting States in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless :

- (a) the individual or firm has a fixed base regularly available to the individual or firm in the other Contracting State for the purpose of performing the individual's or the firm's activities, in which case the income may be taxed in that other State but only so much of it as is attributable to activities exercised from that fixed base ; or
- (b) the stay by the individual or, in the case of a firm, by one or more members of the firm (alone or together) in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding 183 days in a year of income, in which case only so much of the income as is derived from the activities of the individual, that member or

those members, as the case may be, in that other State may be taxed in that other State.

(2) The term "professional services" includes services performed in the exercise of independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as in the exercise of the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15

Dependent Personal Services

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by an individual who is a resident of one of the Contracting States in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived from that exercise may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by an individual who is a resident of one of the Contracting States in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the firstmentioned State if :

- (a) the recipient is present in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in a year of income of that other State ;
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other State ; and
- (c) the remuneration is not deductible in determining taxable profits of a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by a resident of one of the Contracting States may be taxed in that State.

ARTICLE 16

Directors' Fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of one of the Contracting States as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17

Entertainers

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by residents of one of the Contracting States as entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, musicians and athletes, from their personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of the personal activities of an entertainer as such accrues not to that entertainer but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer are exercised.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), income derived by an entertainer who is a resident of one of the Contracting States, from the entertainer's personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first mentioned Contracting State if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) and Articles 7, 14 and 15, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer in the entertainer's capacity as such in one of the Contracting States accrues not to the entertainer but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

ARTICLE 18

Pensions and Annuities

(1) Pensions (not including pensions referred to in Article 19) and annuities paid to a resident of one of the Contracting States shall be taxable only in that State.

(2) The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE 19

Government Service

(1) Remuneration, other than a pension or annuity, paid by one of the Contracting States or a political sub-division or local authority of that State to any individual in respect of services rendered in the discharge of governmental functions shall be taxable only in that State. However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the recipient is a resident of that other State who :

- (a) is a citizen of that State ; or
- (b) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

(2) Any pension paid by, or out of funds created by, one of the Contracting States or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State

or sub-division or authority shall be taxable only in that State. However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient is a resident and a citizen of that other State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply, as appropriate in the circumstances, to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by one of the Contracting States or a political sub-division or local authority thereof.

ARTICLE 20

Professors and Teachers

(1) Where a professor or teacher who is a resident of one of the Contracting States visits the other Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or carrying out advanced study or research at a university, college, school or other educational institution, any remuneration that person receives for such teaching, advanced study or research shall be exempt from tax in that other State to the extent to which such remuneration is, or upon the application of this Article will be, subject to tax in the first mentioned State.

(2) This Article shall not apply to remuneration which a professor or teacher receives for conducting research if the research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

ARTICLE 21

Students and Trainees

Where a student or trainee, who is a resident of one of the Contracting States or who was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State solely for the purpose of the student's or trainee's education or training, receives payments from sources outside that other State for the purpose of the student's or trainees' maintenance, education or training, those payments shall be exempt from tax in that other State.

ARTICLE 22

Income Not Expressly Mentioned

(1) Items of income of a resident of one of the Contracting States which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

(2) However, any such income derived by a resident of one of the Contracting States from sources in other Contracting State may also be taxed in that other State.

(3) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income derived by a resident of one of the Contracting States where that income is effectively connected with a permanent establishment or fixed base situated in the other Contracting State. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

ARTICLE 23

Source of Income

(1) Income, profits or gains derived by a resident of one of the Contracting States which, under any one or more of Articles 6 to 8, Articles 10 to 20 and Article 22 may be taxed in the other Contracting State, shall for the purposes of the law of that other State relating to its tax be deemed to be income from sources in that other State.

(2) Income, profits or gains derived by a resident of one of the Contracting States which, under any one or more of Articles 6 to 8, Articles 10 to 20 and Article 22 may be taxed in the other Contracting State, shall for the purpose of Article 24 and of the law of the first mentioned State relating to its tax be deemed to be income from sources in that other State.

ARTICLE 24

Methods of Elimination of Double Taxation

(1)(a) Subject to the provisions of the law of Australia from time to time in force which relate to the allowance of a credit against Australian tax of tax paid in a country outside Australia (which shall not affect the general principle hereof), Indian tax paid under the law of India and in accordance with this Agreement, whether directly or by deduction, in respect of income derived by a person who is a resident of Australia from sources in India shall be allowed as a credit against Australian tax payable in respect of that income.

(b) Where a company which is a resident of India and is not a resident of Australia for the purposes of Australian tax pays a dividend to a company which is a resident of Australia and which controls directly or indirectly not less than 10 per cent of the voting power of the firstmentioned company, the credit referred to in subparagraph (a) shall include the Indian tax paid by that firstmentioned company in respect of that portion of its profits out of which the dividend is paid.

(2) In paragraph (1), Indian tax paid shall include :

(a) subject to subparagraph (b), an amount equivalent to the amount of any Indian tax forgone which, under the law of India relating to Indian tax and in accordance with this Agreement, would have been payable as Indian tax on income but for an exemption from, or reduction of, Indian tax on that income in accordance with :

(i) section 10(4), 10(15)(iv), 10A, 10B, 80HHC, 80HHD or 80I of the Income tax Act, 1961, insofar as those provisions were in force on, and have not been modified since, the date of signature of this Agreement, or have been modified

only in minor respects so as not to affect their general character ; or

(ii) any other provision which may subsequently be made granting an exemption from or reduction of Indian tax which the Treasurer of Australia and the Minister of Finance of India agree from time to time in letters exchanged for this purpose to be of a substantially similar character if that provision has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character ; and

(b) in the case of interest derived by a resident of Australia which is exempted from Indian tax under the provisions referred to in subparagraph (a), the amount which would have been payable as Indian tax if the interest had not been so exempt and if the tax referred to in paragraph (2) of Article 11 did not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Paragraph (2) shall apply only in relation to income derived in any of the first 10 years of income in relation to which this Agreement has effect under subparagraph (1)(a)(ii) of Article 28 or in any later year of income that may be agreed by the Contracting States in letters exchanged for this purpose.

(4) In the case of India, double taxation shall be avoided as follows :

(a) the amount of Australian tax paid under the laws of Australia and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India in respect of income from sources within Australia which has been subjected to tax both in India and Australia shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax ; and

(b) for the purposes of the credit referred to in subparagraph (a) above, where the resident of India is a company by which surtax is payable, the credit to be allowed against Indian tax shall be allowed in the first instance against the income tax payable by the company in India and, as to the balance, if any, against the surtax payable by it in India.

(5) Where a resident of one of the Contracting States derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement shall be taxable only in the other Contracting State, the firstmentioned State may take that income into account in calculating the amount of its tax payable on the remaining income of that resident.

ARTICLE 25

Mutual Agreement Procedure

(1) Where a person who is a resident of one of the Contracting States considers that the actions of the taxation authority of one or both of the Contracting States result or will result for the person in taxation not in accordance with this Agreement, the person may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present a case to the competent authority of the Contracting State of which the person is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action giving rise to taxation not in accordance with this Agreement.

(2) The competent authority shall endeavour, if the claim appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Agreement. The solution so reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall jointly endeavour to resolve any difficulties or doubts arising as to the application of this Agreement.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of giving effect to the provisions of this Agreement.

ARTICLE 26

Exchange of Information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning the taxes to which this Agreement applies insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement, or for the prevention of evasion or avoidance of, or fraud in relation to, such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by the competent authority of a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes to which this Agreement applies and shall be used only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

(2) The competent authorities may, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made. The exchange of information shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases, or both. The competent authorities of the Contracting

States may agree from time to time on the list of the information which shall be furnished on a routine basis.

(3) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on the competent authority of a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or to supply information the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 27

Diplomatic and Consular Officials

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special international agreements.

ARTICLE 28

Entry into Force

(1) This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting States exchange notes through the diplomatic channel notifying each other that the last of such things has been done as is necessary to give this Agreement the force of law in Australia and in India, as the case may be, and thereupon this Agreement shall have effect :

(a) in Australia :

- (i) in respect of withholding tax on income that is derived by a non-resident, in relation to income derived on or after 1 July in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force ; and
- (ii) in respect of other Australian tax, in relation to income, profits or gains of any year of income beginning on or after 1 July in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force ;

(b) in India, in respect of income, profits or gains arising in any year of income beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force.

(2) The Agreement made between the Government of Australia and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation of Income derived from International Air

Transport signed at Canberra on 31 May 1983 (in this Article called "the 1983 Agreement") shall cease to have effect with respect to taxes to which this Agreement applies when the provisions of this Agreement become effective in accordance with paragraph (1).

(3) The 1983 Agreement shall terminate on the expiration of the last date on which it has effect in accordance with the foregoing provisions of this Article.

ARTICLE 29

Termination

This Agreement shall continue in effect indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30 June in any calendar year beginning after the expiration of 5 years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State through the diplomatic channel written notice of cease to be effective :

(a) in Australia :

termination and, in that event, this Agreement shall

- (i) in respect of withholding tax on income that is derived by a non-resident, in relation to income derived on or after 1 July in the calendar year next following that in which the notice of termination is given ; and

- (ii) in respect of other Australian tax, in relation to income, profits or gains of any year of income beginning on or after 1 July in the calendar year next following that in which the notice of termination is given ;

- (b) in India, in respect of income, profits or gains arising in any year of income beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Canberra this Twenty fifth day of July One thousand nine hundred and ninety-one in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic, the English text to be the operative one in any case of doubt.

FOR THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF INDIA :

FOR THE GOVERNMENT OF
AUSTRALIA :

[Notification No. 3984 (F. No. 501/1/79-FTD)]

N. C. JAIN, Jt. Secy.